



2026:AHC:66942

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या- 11662 वर्ष 2026

सूरजपाल और 2 अन्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सुदर्शन सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, राकेश कुमार सिंह

न्यायालय सं - 80

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आज दायर किए गए पूरक हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदकों के अधिवक्ता, सूचनाकर्ता की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता और राज्य प्रतिपक्षियों की ओर से उपस्थित होने वाले अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
3. आवेदक संख्या-1 और 2 के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 22.11.2023 और आवेदक संख्या-1 और 2 के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 3.11.2023 को रद्द करने के लिए प्रस्तुत आवेदन दायर किया गया है, साथ ही एस.टी. संख्या-1052 वर्ष 2013 (राज्य बनाम विजय) और एस.टी. संख्या-669 वर्ष 2016 (राज्य बनाम सूरजपाल और अन्य) की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही दोनों को धारा 363, 366, 366, 376 (2)(जी), 368 भ०द०वि०, थाना-इज्जतनगर, जिला बरेली के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी., बरेली के समक्ष लंबित है।
4. आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवाह आवेदक संख्या-1 और प्रस्तुत मामले की पीड़िता के बीच संपन्न हो गया है और विवाहित जोड़े के विवाह से दो बच्चे पैदा हुए हैं। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उन्होंने 7.2.2026 को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समझौता किया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि 7.2.2026 को विवाह, बच्चों के जन्म और समझौते को देखते हुए, प्रस्तुत आवेदकों के खिलाफ कार्यवाही रद्द की जाए।

4. सूचनाकर्ता के अधिवक्ता भी उपस्थित हुए हैं और आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्क को स्वीकार कर लिया है।

5. हालांकि, अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि यह घटना वर्ष 2011 में हुई थी। इस मामले में आरोप पत्र 10.11.2013 को प्रस्तुत किया गया था। आवेदक नियमित रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हो रहे थे। पीड़िता का बयान 16.8.2016 को विचारण न्यायालय में अ०सा०-3 के रूप में दर्ज किया गया है और उसने आवेदकों के खिलाफ बयान दिया है। उसने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी व्यक्तियों/आवेदकों द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। अब, मामला बहस के लिए तय किया गया है। यदि विवाह 31.10.2011 को संपन्न हुआ होता, तो पीड़िता ने 16.8.2016 को आवेदकों के खिलाफ बयान नहीं दिया होता। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तुत आवेदन के साथ कोई विवाह प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है और केवल हलफनामा, कथित रूप से पीड़िता द्वारा शपथ लिया गया है, को सबूत के रूप में जोड़ा गया है।

6. अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि **नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और (2014) 6 एस.सी.सी. 466** में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए, समझौते को मुकदमे के अग्रिम चरण में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तुत आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

6. मैंने पक्षगण के अधिवक्ता को सुना है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि आरोप पत्र वर्ष 2013 में प्रस्तुत किया गया था और आवेदकों को वर्ष 2013 और 2016 में बहुत पहले तलब किया गया था। प्रस्तुत आवेदन को स्थानांतरित करने में देरी को किसी भी प्रस्तर में ठीक से नहीं समझाया गया है। यह न्यायालय 13 वर्षों के बाद समन आदेश को रद्द नहीं कर सकता है,



खासकर जब मुकदमा अग्रिम चरण में हो। पूरक हलफनामे के साथ संलग्न आरोप-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मामला 22.1.2026 को बहस के लिए तय किया गया था और अब बहस के लिए 10.4.2026 तय किया गया है। इस बीच, विचारण न्यायालय द्वारा कई तारीखें तय की गईं, लेकिन एक या किसी अन्य कारण से पक्षों के अधिवक्ता द्वारा तर्क आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

8. नरिंदर सिंह (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किए गए पर विचार किया है और आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। नरिंदर सिंह (उपरोक्त) का प्रासंगिक प्रस्तर-यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"31. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित सिद्धांतों को सारांशित करते हैं और निर्धारित करते हैं जिनके द्वारा उच्च न्यायालय को पक्षों के बीच समझौते के लिए पर्याप्त उपचार देने और समझौते को स्वीकार करते समय संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने में मार्गदर्शन किया जाएगा और कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा या आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के निर्देश के साथ समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जाएगा:

(i) संहिता की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्ति को उस शक्ति से अलग किया जाना है जो संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को कम करने के लिए न्यायालय में निहित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संहिता की धारा 482 के तहत, उच्च न्यायालय के पास उन मामलों में भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है जो शमनीय नहीं हैं, जहां पक्षों ने मामले को आपस में सुलझाया है। हालाँकि, इस शक्ति का प्रयोग संयम से और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

(ii) जब पक्ष समझौते पर पहुंच जाते हैं और उस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की जाती है, तो ऐसे मामलों में मार्गदर्शक कारक यह सुनिश्चित करना होगा:

(i) न्याय का अंत, या



(ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को उपरोक्त दो उद्देश्यों में से किसी एक पर एक राय बनाना है।

(III) ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाता है जिनमें मानसिक भ्रष्टता के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हैं। ऐसे अपराध प्रकृति में निजी नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानून के तहत किए गए कथित अपराधों के लिए या उस क्षमता में काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों को केवल पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

(IV) दूसरी ओर, उन आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया जाना चाहिए जिनमें अत्यधिक और मुख्य रूप से सिविल चरित्र है, विशेष रूप से वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होने वाले या वैवाहिक संबंधों या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न होने वाले मामलों को तब रद्द कर दिया जाना चाहिए जब पक्षकारों ने अपने पूरे विवादों को आपस में सुलझा लिया हो।

(V) अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को इस बात की जांच करनी है कि क्या दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामलों को जारी रखने से अभियुक्त पर बहुत अधिक अत्याचार और पूर्वाग्रह होगा और आपराधिक मामलों को रद्द न करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

(VI) भ०द०वि० की धारा 307 के तहत अपराध जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आएंगे और इसलिए इसे आम तौर पर समाज के खिलाफ अपराध के रूप में माना जाना चाहिए, न कि केवल व्यक्ति के खिलाफ। हालांकि, उच्च न्यायालय अपने फैसले को केवल इसलिए नहीं रोकेगा क्योंकि प्राथमिकी में भ०द०वि० की धारा 307 का उल्लेख है या इस प्रावधान के तहत आरोप तय किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए यह जांच करने का अधिकार होगा कि क्या भ०द०वि० की धारा 307 को शामिल किया गया है या अभियोजन पक्ष ने



पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं, जो साबित होने पर भ०द०वि० की धारा 307 के तहत आरोप साबित हो जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह चोट की प्रकृति को ध्यान में रखेगा कि क्या ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/प्रतिनिधि अंगों पर लगी है, इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति आदि। पीड़ित को लगी चोटों के संबंध में मेडिकल रिपोर्ट आम तौर पर मार्गदर्शक कारक हो सकती हैं। इस प्रथम दृष्टया विश्लेषण के आधार पर, उच्च न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि क्या दोषसिद्धि की प्रबल संभावना है या दोषसिद्धि की संभावना कम और धूमिल है। पहले मामले में वह समझौते को स्वीकार करने और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर सकता है जबकि बाद के मामले में उच्च न्यायालय के लिए पक्षों के बीच पूर्ण समझौते के आधार पर अपराध को कम करने वाली याचिका को स्वीकार करने की अनुमति होगी। इस स्तर पर, न्यायालय इस तथ्य से भी प्रभावित हो सकता है कि पक्षों के बीच समझौते के परिणामस्वरूप उनके बीच सामंजस्य स्थापित होने जा रहा है जिससे उनके भविष्य के संबंधों में सुधार हो सकता है।

(VII) संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना है या नहीं, यह तय करते समय निपटान का समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे मामले जहां अपराध के कथित कमीशन के तुरंत बाद समझौता हो जाता है और मामला अभी भी जांच के अधीन है, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही/जांच को रद्द करने के लिए समझौते को स्वीकार करने में उदार हो सकता है। यही कारण है कि इस स्तर पर जांच अभी भी जारी है और यहां तक कि आरोप पत्र भी दायर नहीं किया गया है। इसी तरह, वे मामले जहां आरोप तय किए गए हैं लेकिन सबूत अभी तक शुरू नहीं हुए हैं या सबूत अभी भी प्रारंभिक अवस्था में हैं, उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का अनुकूल रूप से प्रयोग करने में उदारता दिखा सकता है, लेकिन ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों/सामग्री के प्रथम दृष्टया मूल्यांकन के बाद। दूसरी ओर, जहां अभियोजन पक्ष के साक्ष्य लगभग पूरे हो गए हैं या साक्ष्य के समापन के बाद मामला बहस के चरण में है, आम तौर पर



उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में विचारण न्यायालय मामले को अंतिम रूप से गुण-दोष के आधार पर तय करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में होगा कि भ०द०वि० की धारा 307 के तहत अपराध किया गया है या नहीं। इसी तरह, उन मामलों में जहां विचारण न्यायालय द्वारा पहले से ही दोषसिद्धि दर्ज की जा चुकी है और मामला उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलीय चरण में है, पक्षगण के बीच केवल समझौता इसे स्वीकार करने का आधार नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप अपराधी को बरी कर दिया जाएगा जिसे पहले ही विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है। यहां भ०द०वि० की धारा 307 के तहत आरोप साबित होता है और दोषसिद्धि पहले से ही एक जघन्य अपराध के लिए दर्ज होती है और इसलिए, इस तरह के अपराध के दोषी पाए जाने वाले दोषी को बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है। (महत्व सन्निविष्ट)

8. इस मामले को देखते हुए, प्रस्तुत आवेदन में योग्यता का अभाव है और इसे खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

9. लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

मार्च 31, 2026

ललित शुक्ला

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)